

स्थानीय शासन से राष्ट्रीय राजनीति तक: नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता के बदलते स्वरूप का अध्ययन

डॉ. दलीप कुमार

सहायक प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) राजकीय डिग्री कॉलेज, गंगेश्वरी, अमरोहा- 244255

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन “स्थानीय शासन से राष्ट्रीय राजनीति तक: नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता के बदलते स्वरूप का अध्ययन” का उद्देश्य नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता के स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करना तथा राजनीतिक जागरूकता, सूचना-संपर्क, राजनीतिक चर्चा और डिजिटल सहभागिता जैसे कारकों के साथ उसके संबंधों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में उदाहरणात्मक रूप से 300 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया। अध्ययन के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से स्थानीय शासन, ग्राम सभा, प्रतिनिधि-संपर्क, मतदान, राजनीतिक मुद्दों की जानकारी, राजनीतिक चर्चा, डिजिटल राजनीतिक गतिविधि तथा राजनीतिक प्रभावशीलता से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त की गईं। परिणामों से स्थानीय राजनीतिक सहभागिता का समग्र माध्य 3.10, राज्य राजनीतिक सहभागिता का 3.18 तथा राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता का 3.36 पाया गया। सहसंबंध विश्लेषण में स्थानीय एवं राज्य सहभागिता के बीच सकारात्मक संबंध तथा राज्य एवं राष्ट्रीय सहभागिता के बीच अपेक्षाकृत मजबूत सकारात्मक संबंध प्राप्त हुआ। राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक चर्चा, सूचना-संपर्क और डिजिटल सहभागिता का भी राजनीतिक सहभागिता से सकारात्मक संबंध पाया गया। बहु-प्रतिगमन मॉडल में राजनीतिक जागरूकता, स्थानीय सहभागिता, राजनीतिक प्रभावशीलता, राजनीतिक चर्चा और डिजिटल सहभागिता महत्वपूर्ण पूर्वानुमानक पाए गए। अध्ययन से संकेत मिलता है कि आधुनिक राजनीतिक सहभागिता बहुस्तरीय तथा बहु-माध्यमीय स्वरूप ग्रहण कर रही है।

मुख्य शब्द: राजनीतिक सहभागिता, स्थानीय शासन, पंचायती राज, राजनीतिक जागरूकता, नागरिक सहभागिता, डिजिटल राजनीति, लोकतांत्रिक सहभागिता

प्रस्तावना

लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल चुनावों के आयोजन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के चयन में निहित नहीं होती, बल्कि नागरिकों की निरंतर, जागरूक और विभिन्न स्तरों पर सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में भी निहित होती है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक स्थानीय समस्याओं, ग्राम पंचायतों और नगर निकायों से लेकर राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय संसद तक विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक सहभागिता को केवल मतदान के व्यवहार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक चर्चा, चुनावी मुद्दों की जानकारी, ग्राम सभा या स्थानीय बैठकों में भागीदारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क, राजनीतिक संगठनों से जुड़ाव, सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता तथा डिजिटल माध्यमों पर राजनीतिक अभिव्यक्ति भी राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण रूप हैं। भारत में स्थानीय शासन को संवैधानिक आधार मिलने के बाद नागरिक सहभागिता का दायरा संस्थागत रूप से और व्यापक हुआ। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के बाद स्थानीय स्वशासन को शासन की तीसरी परत के रूप में विकसित किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएँ और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएँ शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार स्थानीय शासन का उद्देश्य विकेंद्रीकरण तथा सहभागी स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना है।

- **राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा-** राजनीतिक सहभागिता का अर्थ उन गतिविधियों से है जिनके माध्यम से नागरिक शासन, सार्वजनिक नीतियों और राजनीतिक निर्णय-निर्माण को प्रभावित करने या उसमें भाग लेने का

प्रयास करते हैं। इसका सबसे सामान्य रूप मतदान है, लेकिन इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों अथवा संगठनों की गतिविधियों में भाग लेना, चुनावी अभियान से जुड़ना, जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना, स्थानीय समस्याओं को प्रशासन के सामने रखना और सार्वजनिक आंदोलनों में भाग लेना भी इसके महत्वपूर्ण रूप हैं।

- समकालीन समय में राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप और अधिक विस्तृत हुआ है। डिजिटल माध्यमों ने नागरिकों को राजनीतिक सूचना प्राप्त करने, विचार व्यक्त करने, राजनीतिक सामग्री साझा करने और सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस प्रकार पारंपरिक और डिजिटल दोनों प्रकार की सहभागिता को वर्तमान राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में सम्मिलित करना आवश्यक हो गया है।
- **स्थानीय शासन में नागरिक सहभागिता-** स्थानीय शासन नागरिक और सरकार के बीच सबसे निकट का संस्थागत संपर्क प्रस्तुत करता है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका तथा नगर निगम जैसी संस्थाएँ नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं और स्थानीय विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। स्थानीय स्तर पर नागरिक सड़क, जल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाओं और विकास योजनाओं जैसे विषयों पर अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को व्यक्त कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय स्थानीय स्वशासन को विकेंद्रीकृत और सहभागी बनाने तथा पंचायतों में जवाबदेही और समावेशी विकास को बढ़ावा देने को अपने प्रमुख उद्देश्यों में रखता है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सहभागिता नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर सकती है। ग्राम सभा में भाग लेना, पंचायत बैठकों में उपस्थित होना, निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क करना और स्थानीय विकास कार्यों की निगरानी करना नागरिक सहभागिता के ऐसे रूप हैं जो लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया से आगे ले जाते हैं।
- **राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता-** नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहती। राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय संसद के चुनावों में मतदान, राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भागीदारी, चुनावी अभियानों में सहभागिता, राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा तथा जनप्रतिनिधियों से संवाद राज्य और राष्ट्रीय राजनीति से नागरिकों के जुड़ाव को प्रदर्शित करते हैं। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के व्यापक स्तर को 2024 के लोकसभा चुनाव के आँकड़ों से भी समझा जा सकता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग **64.6 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया**, जिसे आयोग ने अभूतपूर्व भागीदारी के रूप में दर्ज किया। इससे स्पष्ट होता है कि मतदान आज भी राजनीतिक सहभागिता का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन मतदान के अतिरिक्त नागरिक किस प्रकार राष्ट्रीय मुद्दों को समझते हैं, राजनीतिक दलों से जुड़ते हैं, डिजिटल माध्यमों पर चर्चा करते हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हैं—इन पहलुओं का अध्ययन राजनीतिक सहभागिता के बदलते स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है।
- **स्थानीय से राष्ट्रीय राजनीति की ओर सहभागिता का विस्तार-** स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय राजनीति को पूर्णतः अलग-अलग राजनीतिक क्षेत्र मानना उचित नहीं होगा। नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े स्थानीय मुद्दे कई बार राज्य और राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएँ स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाती हैं, लेकिन इनके लिए नीतिगत निर्णय उच्चतर शासन स्तरों पर भी लिए जाते हैं। इस प्रकार स्थानीय राजनीतिक अनुभव नागरिकों की व्यापक राजनीतिक समझ को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाएँ और नीतियाँ स्थानीय स्तर पर नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक राजनीतिक सहभागिता के बीच संभावित संबंध का अध्ययन महत्वपूर्ण है।
- **राजनीतिक सहभागिता के बदलते माध्यम-** पारंपरिक राजनीतिक सहभागिता में मतदान, राजनीतिक बैठक, चुनावी सभा, राजनीतिक दल की सदस्यता और जनप्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संपर्क जैसे माध्यम प्रमुख रहे हैं। डिजिटल युग में इनके साथ ऑनलाइन समाचार, सामाजिक माध्यम, डिजिटल अभियान, राजनीतिक वीडियो, ऑनलाइन चर्चाएँ और डिजिटल नागरिक अभियानों ने नए अवसर पैदा किए हैं। हालाँकि डिजिटल सहभागिता को वास्तविक राजनीतिक सहभागिता का स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता। किसी राजनीतिक सामग्री को देखना या साझा करना और किसी राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना अलग-अलग व्यवहार हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान अध्ययन में राजनीतिक सहभागिता को **बहुआयामी अवधारणा** के रूप में देखना आवश्यक है।

- **नागरिक राजनीतिक सहभागिता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व** - सक्रिय नागरिक सहभागिता लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। जब नागरिक स्थानीय समस्याओं को उठाते हैं, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रतिनिधियों से प्रश्न करते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो शासन और नागरिकों के बीच संवाद की संभावना बढ़ती है। इसी संदर्भ में पंचायती राज मंत्रालय ने 2026 में ग्राम सभा में कम भागीदारी से संबंधित एक राष्ट्रीय अध्ययन प्रकाशित किया है। यह तथ्य स्थानीय लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के प्रश्न की समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाता है।

शोध प्रश्न-“स्थानीय शासन से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति तक नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप में क्या परिवर्तन दिखाई देता है तथा सामाजिक, शैक्षिक एवं सूचना-संबंधी कारक इस बहुस्तरीय राजनीतिक सहभागिता से किस प्रकार संबंधित हैं?”

परिकल्पनाएँ

H₀₁-स्थानीय शासन में नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक सहभागिता के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

H₀₂-विभिन्न शैक्षिक स्तरों वाले नागरिकों की स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता के औसत स्तर में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

H₀₃-राजनीतिक सूचना-संपर्क, राजनीतिक चर्चा एवं डिजिटल राजनीतिक सहभागिता नागरिकों की समग्र राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण पूर्वानुमानक नहीं हैं।

अध्ययन का महत्व

- यह अध्ययन राजनीतिक सहभागिता को केवल मतदान तक सीमित न रखकर स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर नागरिकों की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों को समझने में सहायक होगा।
- स्थानीय शासन नागरिकों और प्रशासन के बीच प्रत्यक्ष संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम है। स्थानीय स्तर पर सहभागिता का अध्ययन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सामाजिक आधारभूमि को समझने में उपयोगी होगा।
- अध्ययन यह समझने में सहायता करेगा कि स्थानीय राजनीतिक अनुभव और गतिविधियाँ व्यापक राजनीतिक सहभागिता से किस प्रकार संबंधित हैं।
- राजनीतिक जानकारी, राजनीतिक चर्चा और निर्णय-निर्माण में सहभागिता नागरिकों को अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को समझने में सहायता कर सकती है।
- अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष मतदाता शिक्षा, नागरिक शिक्षा, स्थानीय शासन में जनसहभागिता और राजनीतिक सूचना कार्यक्रमों के निर्माण में उपयोगी हो सकते हैं।
- डिजिटल माध्यमों ने राजनीतिक सूचना और अभिव्यक्ति के नए अवसर प्रदान किए हैं। अध्ययन पारंपरिक और डिजिटल राजनीतिक सहभागिता के बीच संबंध को समझने में सहायता करेगा।
- पंचायती राज मंत्रालय स्वयं सहभागी और विकेंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन को अपने दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। इसलिए स्थानीय स्तर की नागरिक सहभागिता और व्यापक राजनीतिक सहभागिता के बीच संबंध का अध्ययन समकालीन लोकतांत्रिक शोध के लिए प्रासंगिक है।

अध्ययन की आवश्यकता

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता विभिन्न स्तरों पर दिखाई देती है। सामान्यतः राजनीतिक सहभागिता का मूल्यांकन चुनाव में मतदान जैसे संकेतकों के आधार पर किया जाता है। लेकिन नागरिकों की वास्तविक राजनीतिक सक्रियता को समझने के लिए स्थानीय शासन, राज्य राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अलग-

अलग तथा संयुक्त सहभागिता का अध्ययन आवश्यक है। स्थानीय शासन नागरिकों के लिए राजनीतिक प्रक्रिया का सबसे निकटतम स्तर है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और नगर निकायों में नागरिक स्थानीय समस्याओं, विकास योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर भाग ले सकते हैं। इसके बाद राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक मतदान, राजनीतिक चर्चा, प्रतिनिधियों से संपर्क तथा राजनीतिक अभियानों के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन सभी स्तरों पर सहभागिता का स्वरूप समान होना आवश्यक नहीं है। कोई नागरिक स्थानीय शासन में सक्रिय हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में सीमित रुचि रख सकता है; इसी प्रकार कोई नागरिक राष्ट्रीय चुनावों में सक्रिय रुचि रख सकता है लेकिन स्थानीय संस्थाओं की बैठकों में भाग न लेता हो। डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने इस संबंध को और जटिल बनाया है। अब नागरिक स्थानीय समस्याओं को सामाजिक माध्यमों पर उठा सकते हैं और उसी माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए पारंपरिक और डिजिटल राजनीतिक सहभागिता को एक साथ समझना आवश्यक है।

शोध-अंतराल

- अनेक अध्ययन स्थानीय शासन या चुनावी राजनीति जैसे किसी एक स्तर पर केंद्रित होते हैं। स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक नागरिक सहभागिता के क्रमिक एवं तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता बनी हुई है।
- केवल मतदान के आधार पर राजनीतिक सहभागिता का मूल्यांकन नागरिकों की राजनीतिक सक्रियता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। राजनीतिक चर्चा, प्रतिनिधियों से संपर्क, स्थानीय बैठकों में सहभागिता और डिजिटल राजनीतिक गतिविधियों को भी सम्मिलित करना आवश्यक है।
- यह महत्वपूर्ण शोध प्रश्न है कि क्या स्थानीय शासन में सक्रिय नागरिक राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में भी अधिक सक्रिय होते हैं। इस संबंध का सांख्यिकीय परीक्षण अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शोध दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है।
- सामाजिक माध्यमों और डिजिटल राजनीतिक संचार ने राजनीतिक सहभागिता के नए रूप विकसित किए हैं। इन नए रूपों को स्थानीय और पारंपरिक राजनीतिक सहभागिता के साथ जोड़कर अध्ययन करने की आवश्यकता है।
- शिक्षा, आयु, आय, व्यवसाय, ग्रामीण-शहरी पृष्ठभूमि और राजनीतिक सूचना तक पहुँच राजनीतिक सहभागिता में अंतर पैदा कर सकते हैं। इन कारकों को संयुक्त रूप से विश्लेषित करने की आवश्यकता है।
- राजनीतिक सूचना प्राप्त करना और राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हो सकती हैं। इसलिए सूचना-संपर्क और वास्तविक सहभागिता के बीच संबंध का अध्ययन आवश्यक है।
- स्थानीय शासन को केवल प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखने के बजाय नागरिक राजनीतिक सीख और व्यापक लोकतांत्रिक सहभागिता के संभावित आधार के रूप में अध्ययन करना इस शोध को एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अध्ययन की परिसीमाएँ

1. अध्ययन का मुख्य केंद्र **स्थानीय शासन से राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति तक नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता** रहेगा।
2. स्थानीय राजनीतिक सहभागिता में ग्राम सभा/स्थानीय निकाय की बैठकों में भागीदारी, स्थानीय समस्याएँ उठाना, प्रतिनिधियों से संपर्क और स्थानीय विकास गतिविधियों में सहभागिता शामिल की जाएगी।
3. राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता में मतदान, राजनीतिक चर्चा, चुनावी मुद्दों की जानकारी, राजनीतिक दलों/अभियानों से संपर्क तथा प्रतिनिधियों से संवाद जैसे आयाम शामिल किए जा सकते हैं।
4. डिजिटल राजनीतिक सहभागिता में ऑनलाइन राजनीतिक समाचार, सामाजिक माध्यमों पर राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक सामग्री साझा करना तथा डिजिटल नागरिक अभियानों में भागीदारी जैसे आयाम सम्मिलित किए जा सकते हैं।
5. अध्ययन चयनित भौगोलिक क्षेत्र एवं चयनित नागरिकों तक सीमित रहेगा।
6. अध्ययन में विभिन्न आयु, लिंग, शैक्षिक स्तर, व्यवसाय और आय-वर्ग के नागरिकों को सम्मिलित किया जा सकता है।
7. अध्ययन मुख्यतः **मात्रात्मक सर्वेक्षण पद्धति** पर आधारित रखा जाएगा।
8. अध्ययन किसी विशेष राजनीतिक दल, उम्मीदवार या विचारधारा के पक्ष अथवा विपक्ष का मूल्यांकन नहीं करेगा।

9. अध्ययन का उद्देश्य नागरिकों की व्यक्तिगत राजनीतिक पसंद का अनुमान लगाना नहीं, बल्कि **राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न स्तरों और रूपों** का अध्ययन करना होगा।
10. स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता की तुलना अध्ययन में निर्धारित मापदंडों एवं प्रश्नावली के आधार पर की जाएगी।
11. यदि अध्ययन में डिजिटल सहभागिता शामिल की जाती है, तो उसे राजनीतिक सूचना, राजनीतिक चर्चा और नागरिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में सीमित रखा जाएगा।
12. अध्ययन के निष्कर्ष चयनित प्रतिदर्श की सामाजिक एवं भौगोलिक विशेषताओं से प्रभावित हो सकते हैं; इसलिए इन्हें पूरे भारत के नागरिकों पर सीधे सामान्यीकृत नहीं किया जाएगा।

साहित्य समीक्षा

राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक शासन की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नागरिक केवल मतदान ही नहीं करते, बल्कि राजनीतिक सूचना प्राप्त करते हैं, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, प्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं, स्थानीय संस्थाओं की बैठकों में भाग लेते हैं तथा विभिन्न सामुदायिक एवं डिजिटल माध्यमों से अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति करते हैं। Verba, Nie और Kim (1978) ने राजनीतिक सहभागिता को विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से समझाया और यह स्पष्ट किया कि नागरिकों की सहभागिता केवल चुनावी व्यवहार तक सीमित नहीं होती। उनके अध्ययन ने मतदान, राजनीतिक अभियान, सामूहिक गतिविधि तथा सार्वजनिक अधिकारियों से संपर्क जैसे विभिन्न रूपों को राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण आयामों के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय संदर्भ में स्थानीय शासन राजनीतिक सहभागिता का महत्वपूर्ण आधार है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ और स्थानीय स्तर पर नागरिक सहभागिता के लिए ग्राम सभा जैसी संस्थागत व्यवस्था विकसित हुई। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य विकेंद्रीकृत एवं सहभागी शासन को मजबूत करना है। वर्तमान संदर्भ में भी ग्राम सभा में नागरिकों की वास्तविक भागीदारी एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। वर्ष 2026 में पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में ग्राम सभा में कम भागीदारी पर एक राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की है। Putnam (1993) ने सामाजिक पूँजी, नागरिक नेटवर्क और संस्थागत प्रदर्शन के बीच संबंध को रेखांकित किया। उनके अनुसार नागरिकों के बीच विश्वास, सहयोग और सामुदायिक नेटवर्क लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी संचालन में योगदान कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से स्थानीय शासन में भागीदारी केवल प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि नागरिक क्षमता एवं सामाजिक संबंधों के विकास की प्रक्रिया भी है। भारत में राजनीतिक सहभागिता के चुनावी आयाम को समझने के लिए निर्वाचन आयोग के आँकड़े महत्वपूर्ण हैं। निर्वाचन आयोग के 2024 के आँकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 66.10 प्रतिशत रहा और लगभग 64.6 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया। यह तथ्य दर्शाता है कि चुनावी सहभागिता भारतीय लोकतंत्र में व्यापक है, किंतु मतदान को राजनीतिक सहभागिता का पूर्ण प्रतिनिधि मानना पर्याप्त नहीं होगा। Dalton (2008) ने आधुनिक लोकतंत्रों में नागरिक सहभागिता के बदलते स्वरूप पर बल देते हुए बताया कि राजनीतिक सहभागिता पारंपरिक चुनावी व्यवहार से आगे बढ़कर मुद्दा-आधारित, प्रत्यक्ष तथा गैर-पारंपरिक गतिविधियों की ओर बढ़ रही है। इसी प्रकार Norris (2002) ने राजनीतिक संचार एवं नागरिक सहभागिता के बदलते माध्यमों का अध्ययन किया और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार को राजनीतिक संपर्क के नए अवसरों से जोड़ा। डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने स्थानीय से राष्ट्रीय राजनीति तक नागरिक सहभागिता की प्रकृति को प्रभावित किया है। इंटरनेट, सामाजिक माध्यम, ऑनलाइन समाचार, डिजिटल अभियान और राजनीतिक चर्चा मंच नागरिकों को राजनीतिक सूचना प्राप्त करने तथा सार्वजनिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के नए अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि डिजिटल सहभागिता की उपलब्धता अपने-आप में समान राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित नहीं करती; शिक्षा, डिजिटल दक्षता, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक रुचि और सूचना की विश्वसनीयता जैसे कारक भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अध्ययन-साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सहभागिता को बहुस्तरीय अवधारणा के रूप में समझना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर नागरिकों का अनुभव प्रतिनिधियों, ग्राम सभा और स्थानीय विकास कार्यों से जुड़ा होता है, जबकि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव, राजनीतिक दल, सार्वजनिक नीतियाँ, मीडिया और डिजिटल संचार अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्तमान अध्ययन इसी अंतर-संबंध को एक ही विश्लेषणात्मक ढाँचे में समझने का प्रयास करता है। विशेष रूप से स्थानीय सहभागिता, राजनीतिक जागरूकता, सूचना-संपर्क, राजनीतिक चर्चा, डिजिटल सहभागिता और राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता के बीच संबंध का अध्ययन साहित्य में एक उपयोगी विस्तार प्रस्तुत करता है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन “स्थानीय शासन से राष्ट्रीय राजनीति तक: नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता के बदलते स्वरूप का अध्ययन” वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण शोध प्रारूप पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता को केवल मतदान तक सीमित न रखते हुए स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उसके विभिन्न आयामों का अध्ययन करना है। अध्ययन में उदाहरणात्मक रूप से 300 उत्तरदाताओं का प्रतिदर्श लिया गया है। उत्तरदाताओं का चयन विभिन्न आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, आय तथा ग्रामीण-शहरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया गया। अध्ययन के लिए संरचित प्रश्नावली का निर्माण किया गया, जिसमें सामाजिक-जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ राजनीतिक जागरूकता, स्थानीय शासन की जानकारी, ग्राम सभा/स्थानीय बैठक में सहभागिता, प्रतिनिधियों से संपर्क, स्थानीय समस्याओं पर अभिव्यक्ति, राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों की जानकारी, मतदान व्यवहार, राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक सूचना-संपर्क, डिजिटल राजनीतिक सहभागिता तथा राजनीतिक प्रभावशीलता से संबंधित मर्दाने शामिल की गईं। अधिकांश सहभागिता संबंधी मर्दाने को पाँच-बिंदु मापनी पर मापा गया, जिसमें उच्च अंक अधिक सहभागिता का संकेत देते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आवृत्ति, प्रतिशत, माध्य एवं मानक विचलन का प्रयोग किया गया। विभिन्न सामाजिक समूहों में राजनीतिक सहभागिता के अंतर का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र नमूना परीक्षण तथा एक-मार्गीय प्रसरण विश्लेषण का उपयोग किया गया। स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता तथा राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक चर्चा, सूचना-संपर्क और डिजिटल सहभागिता के बीच संबंधों को जानने के लिए पियर्सन सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया गया। समग्र राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण पूर्वानुमानकों की पहचान के लिए बहु-प्रतिगमन विश्लेषण किया गया। सांख्यिकीय परीक्षणों में 0.05 का सार्थकता स्तर अपनाया गया। अध्ययन में स्थानीय सहभागिता को स्वतंत्र रूप से तथा राज्य एवं राष्ट्रीय सहभागिता के साथ तुलनात्मक रूप से देखा गया। अध्ययन का विश्लेषण यह समझने पर केंद्रित है कि क्या स्थानीय राजनीतिक अनुभव व्यापक राजनीतिक सहभागिता से संबंधित है तथा शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता, सूचना-संपर्क, राजनीतिक चर्चा और डिजिटल माध्यम नागरिकों की बहुस्तरीय राजनीतिक सहभागिता को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1: उत्तरदाताओं की सामाजिक-जनसांख्यिकीय एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि का विस्तृत वितरण

क्रम	चर	श्रेणी	आवृत्ति (f)	प्रतिशत (%)
1	लिंग	पुरुष	162	54.0
		महिला	132	44.0
		अन्य	6	2.0
2	आयु	18-30 वर्ष	60	20.0
		31-40 वर्ष	72	24.0
		41-50 वर्ष	78	26.0
		51-60 वर्ष	54	18.0
		61 वर्ष से अधिक	36	12.0
3	शिक्षा	अशिक्षित	30	10.0
		प्राथमिक	42	14.0
		माध्यमिक	66	22.0
		उच्च माध्यमिक	60	20.0
		स्नातक	66	22.0
		स्नातकोत्तर एवं अधिक	36	12.0
4	निवास	ग्रामीण	156	52.0
		अर्ध-शहरी	72	24.0
		शहरी	72	24.0
5	व्यवसाय	कृषि	78	26.0

		कृषि मजदूरी	42	14.0
		निजी/स्वरोजगार	66	22.0
		सरकारी सेवा	36	12.0
		गृहकार्य	42	14.0
		अन्य	36	12.0
6	मासिक आय	₹10,000 से कम	66	22.0
		₹10,001-20,000	90	30.0
		₹20,001-30,000	72	24.0
		₹30,001-50,000	48	16.0
		₹50,000 से अधिक	24	8.0
7	राजनीतिक चर्चा	निम्न	72	24.0
		मध्यम	138	46.0
		उच्च	90	30.0
8	राजनीतिक सूचना का नियमित संपर्क	निम्न	66	22.0
		मध्यम	132	44.0
		उच्च	102	34.0

तालिका 1 में अध्ययन में सम्मिलित 300 उत्तरदाताओं की सामाजिक-जनसांख्यिकीय तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। लिंग के आधार पर 54 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष, 44 प्रतिशत महिला तथा 2 प्रतिशत अन्य श्रेणी से संबंधित हैं। इस प्रकार प्रतिदर्श में दोनों प्रमुख लिंग समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। आयु-वितरण में 41-50 वर्ष के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 26 प्रतिशत है, जबकि 31-40 वर्ष के 24 प्रतिशत तथा 18-30 वर्ष के 20 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में युवा तथा मध्यम आयु वर्ग दोनों को पर्याप्त स्थान मिला है। शैक्षिक स्थिति में माध्यमिक तथा स्नातक स्तर के उत्तरदाताओं का अनुपात 22-22 प्रतिशत है। उच्च माध्यमिक स्तर के 20 प्रतिशत, स्नातकोत्तर एवं अधिक शिक्षित 12 प्रतिशत तथा अशिक्षित 10 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। निवास के आधार पर ग्रामीण उत्तरदाता 52 प्रतिशत हैं, जबकि अर्ध-शहरी और शहरी उत्तरदाताओं का हिस्सा 24-24 प्रतिशत है। यह वितरण स्थानीय शासन से राष्ट्रीय राजनीति तक सहभागिता के ग्रामीण-शहरी आयामों की तुलना के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है। व्यावसायिक स्थिति में कृषि से जुड़े उत्तरदाता 26 प्रतिशत, निजी/स्वरोजगार 22 प्रतिशत तथा सरकारी सेवा 12 प्रतिशत हैं। आय के स्तर पर ₹10,001-20,000 वर्ग सर्वाधिक 30 प्रतिशत है। राजनीतिक चर्चा के संदर्भ में 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मध्यम स्तर की राजनीतिक चर्चा तथा 30 प्रतिशत ने उच्च स्तर की चर्चा की। राजनीतिक सूचना के नियमित संपर्क में 44 प्रतिशत मध्यम और 34 प्रतिशत उच्च स्तर पर हैं। इस प्रकार प्रतिदर्श में राजनीतिक सूचना एवं चर्चा की पर्याप्त विविधता मौजूद है, जो आगे स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सहभागिता के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है।

तालिका 2: स्थानीय शासन स्तर पर नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता, संस्थागत संपर्क एवं सहभागिता का बहु-परिमाणीय विश्लेषण

क्रम	स्थानीय राजनीतिक सहभागिता का आयाम	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)
1	ग्राम पंचायत/नगर निकाय की जानकारी	3.48	0.91
2	स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका की जानकारी	3.52	0.89
3	ग्राम सभा/स्थानीय बैठक की जानकारी	3.31	0.98
4	स्थानीय विकास योजनाओं की जानकारी	3.27	0.96
5	स्थानीय समस्याओं को प्रतिनिधियों के समक्ष रखना	3.04	1.02
6	ग्राम सभा/स्थानीय बैठक में उपस्थिति	2.96	1.07
7	बैठक में अपनी राय व्यक्त करना	2.71	1.03
8	स्थानीय विकास कार्यों की निगरानी	2.84	1.01
9	स्थानीय बजट/व्यय की जानकारी	2.62	0.94

10	सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना	3.26	0.97
11	स्थानीय प्रतिनिधि से प्रत्यक्ष संपर्क	3.12	1.00
12	स्थानीय शिकायत/समस्या दर्ज करना	2.88	1.04
13	स्थानीय चुनाव में मतदान	3.89	0.83
14	स्थानीय विकास निर्णयों में सहभागिता	2.79	1.00
15	स्थानीय राजनीतिक सहभागिता का समग्र स्तर	3.10	0.68

तालिका 2 स्थानीय शासन के स्तर पर नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करती है। परिणामों से पता चलता है कि स्थानीय चुनाव में मतदान का माध्य 3.89 है, जो सभी संकेतकों में अपेक्षाकृत उच्च है। इससे यह संकेत मिलता है कि मतदान स्थानीय राजनीतिक सहभागिता का अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित रूप है। इसी प्रकार स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका की जानकारी का माध्य 3.52 तथा पंचायत/नगर निकाय की सामान्य जानकारी का माध्य 3.48 है। इससे यह संकेत मिलता है कि संस्थागत जानकारी की तुलना में प्रत्यक्ष निर्णय-निर्माण संबंधी सहभागिता अपेक्षाकृत कम हो सकती है। ग्राम सभा अथवा स्थानीय बैठक की जानकारी का माध्य 3.31 है, जबकि वास्तविक बैठक में उपस्थिति का माध्य 2.96 है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी संस्था के बारे में जानकारी होना और उसकी गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना समान प्रक्रिया नहीं है। स्थानीय प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संपर्क का माध्य 3.12 है, जबकि स्थानीय समस्याओं को प्रतिनिधियों के समक्ष रखने का माध्य 3.04 है। इससे नागरिक-प्रतिनिधि संपर्क का मध्यम स्तर दिखाई देता है। स्थानीय राजनीतिक सहभागिता के अपेक्षाकृत कमजोर आयामों में स्थानीय बजट/व्यय की जानकारी 2.62, बैठक में अपनी राय व्यक्त करना 2.71 और विकास निर्णयों में सहभागिता 2.79 शामिल हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि नागरिक चुनावी गतिविधियों में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय हैं, लेकिन शासन की निरंतर निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी तुलनात्मक रूप से सीमित है। स्थानीय विकास कार्यों की निगरानी का माध्य 2.84 तथा शिकायत दर्ज करने का माध्य 2.88 है। समग्र स्थानीय राजनीतिक सहभागिता का माध्य 3.10 तथा SD 0.68 है। यह मध्यम स्तर की सहभागिता को दर्शाता है। अतः स्थानीय स्तर पर नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, किंतु उनकी सहभागिता मुख्यतः मतदान, सूचना प्राप्त करने और प्रतिनिधियों से संपर्क जैसे अपेक्षाकृत सरल माध्यमों तक अधिक केंद्रित दिखाई देती है।

तालिका 3: राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति में नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न आयामों का तुलनात्मक विश्लेषण

क्रम	राजनीतिक सहभागिता का आयाम	राज्य राजनीति माध्य	SD	राष्ट्रीय राजनीति माध्य	SD
1	चुनावी प्रक्रिया की जानकारी	3.61	0.88	3.74	0.84
2	मतदान की नियमितता	3.82	0.91	3.91	0.82
3	राजनीतिक दलों की जानकारी	3.39	0.96	3.57	0.92
4	उम्मीदवारों की जानकारी	3.28	1.01	3.42	0.97
5	प्रमुख राजनीतिक मुद्दों की जानकारी	3.44	0.94	3.63	0.90
6	चुनावी घोषणापत्र/नीतियों की जानकारी	2.91	1.02	3.12	1.00
7	राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों की तुलना	3.06	1.00	3.24	0.98
8	राजनीतिक चर्चा में भागीदारी	3.18	1.03	3.39	0.96
9	प्रतिनिधियों से संपर्क	2.74	1.04	2.61	1.08
10	चुनावी अभियान से जुड़ाव	2.63	1.06	2.82	1.03
11	राजनीतिक बैठक/सभा में भागीदारी	2.71	1.02	2.76	1.01
12	सार्वजनिक मुद्दों पर राय व्यक्त करना	3.21	0.97	3.38	0.95
13	राजनीतिक दल/संगठन से प्रत्यक्ष जुड़ाव	2.42	1.08	2.51	1.06
14	ऑनलाइन राजनीतिक गतिविधि	3.18	1.11	3.46	1.04
15	समग्र राजनीतिक सहभागिता	3.18	0.67	3.36	0.65

तालिका 3 राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति में नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करती है। समग्र स्तर पर राज्य राजनीति की सहभागिता का माध्य 3.18 तथा राष्ट्रीय राजनीति की सहभागिता का माध्य 3.36 पाया गया है। इस उदाहरणात्मक परिणाम से यह संकेत मिलता है कि उत्तरदाताओं का राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों, चुनावों तथा डिजिटल राजनीतिक गतिविधियों से संपर्क राज्य-स्तरीय प्रत्यक्ष सहभागिता की तुलना में कुछ अधिक है। मतदान की नियमितता दोनों स्तरों पर उच्च है। राज्य स्तर पर इसका माध्य 3.82 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3.91 है। इसी प्रकार चुनावी प्रक्रिया की जानकारी के लिए क्रमशः 3.61 और 3.74 के माध्य प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट होता है कि चुनावी प्रक्रिया राजनीतिक सहभागिता का महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। प्रमुख राजनीतिक मुद्दों की जानकारी भी राष्ट्रीय स्तर पर 3.63 तथा राज्य स्तर पर 3.44 है। इसके विपरीत घोषणापत्र और नीतियों की जानकारी राज्य स्तर पर 2.91 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3.12 है। राजनीतिक दलों या संगठनों से प्रत्यक्ष जुड़ाव दोनों स्तरों पर सबसे कम संकेतकों में है। राज्य स्तर पर इसका माध्य 2.42 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 2.51 है। इससे यह संकेत मिलता है कि नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता आवश्यक रूप से औपचारिक राजनीतिक संगठन की सदस्यता के रूप में प्रकट नहीं होती। ऑनलाइन राजनीतिक गतिविधि का माध्य राष्ट्रीय स्तर पर 3.46 तथा राज्य स्तर पर 3.18 है। इससे डिजिटल माध्यमों के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों से जुड़ाव का अपेक्षाकृत अधिक स्तर दिखाई देता है। प्रतिनिधियों से संपर्क का माध्य राज्य स्तर पर 2.74 और राष्ट्रीय स्तर पर 2.61 है, जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि-संपर्क की सीमित प्रकृति को दर्शाता है। कुल मिलाकर तालिका से यह समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मतदान, मुद्दों की जानकारी, राजनीतिक चर्चा और डिजिटल सहभागिता अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि राज्य एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गहन, प्रत्यक्ष और संगठनात्मक सहभागिता अपेक्षाकृत सीमित है।

तालिका 4: स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता के माध्यमों तथा सूचना-स्रोतों का तुलनात्मक वितरण

क्रम	सूचना/सहभागिता का माध्यम	स्थानीय स्तर माध्य	राज्य स्तर माध्य	राष्ट्रीय स्तर माध्य
1	परिवार एवं रिश्तेदार	3.42	3.31	3.26
2	पड़ोसी/स्थानीय समुदाय	3.38	3.02	2.81
3	स्थानीय प्रतिनिधि	3.51	2.86	2.42
4	ग्राम सभा/स्थानीय बैठक	3.06	2.31	1.98
5	समाचार-पत्र	2.91	3.18	3.34
6	टेलीविजन/रेडियो	3.14	3.36	3.49
7	मोबाइल/इंटरनेट	3.27	3.52	3.71
8	सामाजिक माध्यम	3.08	3.43	3.68
9	ऑनलाइन समाचार	2.94	3.34	3.59
10	राजनीतिक वीडियो	2.76	3.21	3.47
11	मित्र एवं सहकर्मी	3.21	3.26	3.32
12	राजनीतिक चर्चा समूह	2.89	3.12	3.31
13	सरकारी डिजिटल पोर्टल	2.61	2.84	3.02
14	प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संपर्क	3.18	2.71	2.48
15	सूचना-स्रोतों की तुलना/सत्यापन	2.72	2.94	3.16

तालिका 4 से स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में नागरिकों के सूचना-स्रोतों और सहभागिता के माध्यमों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। स्थानीय राजनीति में परिवार, पड़ोसी, स्थानीय प्रतिनिधि तथा ग्राम सभा जैसे प्रत्यक्ष और सामुदायिक स्रोत अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों से सूचना प्राप्त करने का माध्य 3.51 तथा परिवार एवं रिश्तेदारों का 3.42 है। इसके विपरीत राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में स्थानीय प्रतिनिधियों का माध्य घटकर 2.42 हो जाता है। राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति में डिजिटल और जनसंचार माध्यमों का महत्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मोबाइल/इंटरनेट का माध्य स्थानीय स्तर पर 3.27 से बढ़कर राज्य स्तर पर 3.52 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3.71 हो जाता है। इसी प्रकार सामाजिक माध्यम का माध्य 3.08 से बढ़कर 3.43 तथा 3.68 हो जाता है। ऑनलाइन समाचार भी राष्ट्रीय राजनीति में 3.59 के उच्च स्तर तक पहुँचता है। ग्राम सभा अथवा स्थानीय बैठक का माध्य स्थानीय राजनीति में 3.06 है, जबकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर

क्रमशः 2.31 और 1.98 है। यह अपेक्षित भी है क्योंकि ग्राम सभा जैसी संस्थाएँ स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। दूसरी ओर समाचार-पत्र, टेलीविजन/रेडियो, ऑनलाइन समाचार और राजनीतिक वीडियो जैसे माध्यमों का उपयोग राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अधिक दिखाई देता है। सूचना-स्रोतों की तुलना और सत्यापन का माध्य भी स्थानीय स्तर पर 2.72 से बढ़कर राज्य स्तर पर 2.94 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3.16 हुआ है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि जैसे-जैसे राजनीतिक मुद्दे स्थानीय संदर्भ से व्यापक राजनीतिक संदर्भ की ओर बढ़ते हैं, नागरिक विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव कर सकते हैं। समग्र रूप से तालिका यह दर्शाती है कि स्थानीय राजनीति का सूचना-संचार अधिक **प्रत्यक्ष, सामुदायिक और व्यक्ति-आधारित** है, जबकि राज्य एवं विशेषकर राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक संचार अधिक **मीडिया-आधारित, डिजिटल और बहु-स्रोत** स्वरूप ग्रहण करता है। यही परिवर्तन अध्ययन के शीर्षक में वर्णित राजनीतिक सहभागिता के बदलते स्वरूप को समझने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

तालिका 5: सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं डिजिटल विशेषताओं के आधार पर समग्र राजनीतिक सहभागिता में अंतर

चर	श्रेणी	औसत राजनीतिक सहभागिता	F-मूल्य	p-मूल्य
लिंग	पुरुष	3.28	1.74	.178
	महिला	3.34		
	अन्य	3.19		
शिक्षा	अशिक्षित	2.71	10.86	<.001
	प्राथमिक	2.89		
	माध्यमिक	3.12		
	उच्च माध्यमिक	3.31		
	स्नातक	3.54		
	स्नातकोत्तर+	3.71		
निवास	ग्रामीण	3.08	5.42	.005
	अर्ध-शहरी	3.31		
	शहरी	3.49		
आय	₹10,000 से कम	2.96	4.18	.003
	₹10,001–20,000	3.14		
	₹20,001–30,000	3.31		
	₹30,001–50,000	3.47		
	₹50,000+	3.58		
राजनीतिक चर्चा	निम्न	2.82	18.37	<.001
	मध्यम	3.29		
	उच्च	3.63		
डिजिटल सूचना उपयोग	निम्न	2.84	21.46	<.001
	मध्यम	3.27		
	उच्च	3.67		
राजनीतिक सूचना-संपर्क	निम्न	2.79	24.18	<.001
	मध्यम	3.28		
	उच्च	3.69		

तालिका 5 विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सूचना-संबंधी विशेषताओं के आधार पर नागरिकों की समग्र राजनीतिक सहभागिता में अंतर का परीक्षण प्रस्तुत करती है। लिंग के आधार पर पुरुषों का औसत 3.28, महिलाओं का 3.34 तथा अन्य श्रेणी का 3.19 है। F-मूल्य 1.74 तथा $p=.178$ है, जो .05 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर का संकेत नहीं देता। अतः इस उदाहरणात्मक विश्लेषण में केवल लिंग के आधार पर राजनीतिक सहभागिता में महत्वपूर्ण अंतर स्थापित नहीं

होता। शिक्षा के आधार पर स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। अशिक्षित उत्तरदाताओं का औसत 2.71 है, जो स्नातक वर्ग में 3.54 और स्नातकोत्तर एवं अधिक शिक्षित वर्ग में 3.71 तक पहुँचता है। $F=10.86$ तथा $p<.001$ होने से शिक्षा और राजनीतिक सहभागिता के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर का संकेत मिलता है। निवास के आधार पर भी ग्रामीण 3.08, अर्ध-शहरी 3.31 तथा शहरी 3.49 का औसत पाया गया है। आय के साथ राजनीतिक सहभागिता में क्रमिक वृद्धि दिखाई देती है। ₹10,000 से कम आय वर्ग का औसत 2.96 है, जबकि ₹50,000 से अधिक आय वर्ग में यह 3.58 है। $F=4.18$ और $p=.003$ इस अंतर को सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दर्शाते हैं। राजनीतिक चर्चा का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। निम्न चर्चा वर्ग का औसत 2.82, मध्यम वर्ग का 3.29 तथा उच्च चर्चा वर्ग का 3.63 है। इसी प्रकार डिजिटल सूचना उपयोग के निम्न, मध्यम और उच्च वर्गों में क्रमशः 2.84, 3.27 और 3.67 के औसत पाए गए हैं। राजनीतिक सूचना-संपर्क में भी 2.79 से 3.69 तक स्पष्ट वृद्धि दिखाई देती है। इस प्रकार तालिका से संकेत मिलता है कि शिक्षा, आय, निवास, राजनीतिक चर्चा, डिजिटल सूचना उपयोग और राजनीतिक सूचना-संपर्क राजनीतिक सहभागिता से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हो सकते हैं, जबकि लिंग के आधार पर अंतर इस उदाहरणात्मक प्रतिदर्श में महत्वपूर्ण नहीं है।

तालिका 6: स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता तथा प्रमुख सामाजिक-सूचनात्मक चरों के बीच सहसंबंध

क्रम	चर 1	चर 2	सहसंबंध गुणांक (r)	p-मूल्य
1	स्थानीय राजनीतिक सहभागिता	राज्य राजनीतिक सहभागिता	.58	<.001
2	स्थानीय राजनीतिक सहभागिता	राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता	.49	<.001
3	राज्य राजनीतिक सहभागिता	राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता	.67	<.001
4	राजनीतिक जागरूकता	स्थानीय सहभागिता	.55	<.001
5	राजनीतिक जागरूकता	राज्य सहभागिता	.59	<.001
6	राजनीतिक जागरूकता	राष्ट्रीय सहभागिता	.63	<.001
7	राजनीतिक सूचना-संपर्क	स्थानीय सहभागिता	.42	<.001
8	राजनीतिक सूचना-संपर्क	राज्य सहभागिता	.51	<.001
9	राजनीतिक सूचना-संपर्क	राष्ट्रीय सहभागिता	.60	<.001
10	राजनीतिक चर्चा	स्थानीय सहभागिता	.46	<.001
11	राजनीतिक चर्चा	राज्य सहभागिता	.54	<.001
12	राजनीतिक चर्चा	राष्ट्रीय सहभागिता	.62	<.001
13	डिजिटल राजनीतिक सहभागिता	स्थानीय सहभागिता	.34	<.001
14	डिजिटल राजनीतिक सहभागिता	राज्य सहभागिता	.48	<.001
15	डिजिटल राजनीतिक सहभागिता	राष्ट्रीय सहभागिता	.65	<.001
16	राजनीतिक प्रभावशीलता	स्थानीय सहभागिता	.51	<.001
17	राजनीतिक प्रभावशीलता	राज्य सहभागिता	.57	<.001
18	राजनीतिक प्रभावशीलता	राष्ट्रीय सहभागिता	.61	<.001
19	प्रतिनिधि-संपर्क	स्थानीय सहभागिता	.63	<.001
20	समग्र राजनीतिक सहभागिता	बहुस्तरीय सहभागिता	.76	<.001

तालिका 6 स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता के बीच तथा राजनीतिक जागरूकता, सूचना-संपर्क, चर्चा, डिजिटल सहभागिता और राजनीतिक प्रभावशीलता जैसे चरों के साथ उनके संबंध को दर्शाती है। स्थानीय और राज्य राजनीतिक सहभागिता के बीच $r=.58$ तथा स्थानीय और राष्ट्रीय सहभागिता के बीच $r=.49$ पाया गया है। दोनों संबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता के बीच $r=.67$ का अपेक्षाकृत मजबूत सकारात्मक संबंध प्राप्त हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न स्तर पूर्णतः पृथक नहीं हैं। राजनीतिक जागरूकता का स्थानीय सहभागिता के साथ $r=.55$, राज्य सहभागिता के साथ $r=.59$ तथा राष्ट्रीय सहभागिता के साथ $r=.63$ संबंध है। इसका अर्थ यह है कि अधिक राजनीतिक जागरूकता वाले उत्तरदाताओं में व्यापक राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी अधिक पाया जा सकता है। इसी प्रकार राजनीतिक सूचना-संपर्क का राष्ट्रीय सहभागिता के साथ $r=.60$ का संबंध

स्थानीय स्तर के $r=.42$ की तुलना में अधिक है। राजनीतिक चर्चा और सहभागिता के बीच भी सकारात्मक संबंध दिखाई देता है। राजनीतिक चर्चा का स्थानीय स्तर से $r=.46$, राज्य स्तर से $r=.54$ और राष्ट्रीय स्तर से $r=.62$ संबंध है। डिजिटल राजनीतिक सहभागिता का स्थानीय स्तर से संबंध अपेक्षाकृत कम $r=.34$ है, जबकि राज्य स्तर पर $r=.48$ और राष्ट्रीय स्तर पर $r=.65$ है। इससे यह संकेत मिलता है कि डिजिटल माध्यम विशेष रूप से व्यापक राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श से जुड़े हुए हो सकते हैं। राजनीतिक प्रभावशीलता भी तीनों स्तरों पर सकारात्मक रूप से संबंधित है। प्रतिनिधि-संपर्क का स्थानीय सहभागिता के साथ $r=.63$ संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष राजनीतिक संपर्क की भूमिका को दर्शाता है। समग्र बहुस्तरीय राजनीतिक सहभागिता के साथ $r=.76$ का संबंध सभी प्रमुख संकेतकों में उच्चतम संबंधों में है। हालांकि सहसंबंध कारण-कार्य संबंध सिद्ध नहीं करता, फिर भी ये परिणाम यह संकेत देते हैं कि स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता के बीच एक व्यापक राजनीतिक व्यवहारिक निरंतरता मौजूद हो सकती है।

तालिका 7: नागरिकों की समग्र बहुस्तरीय राजनीतिक सहभागिता के पूर्वानुमानकों का बहु-प्रतिगमन विश्लेषण

आश्रित चर: समग्र राजनीतिक सहभागिता

क्रम	स्वतंत्र चर	B	मानक त्रुटि	β	t-मूल्य	p-मूल्य
1	स्थिरांक	.624	.218	—	2.862	.005
2	राजनीतिक जागरूकता	.286	.052	.291	5.500	<.001
3	स्थानीय राजनीतिक सहभागिता	.241	.058	.218	4.155	<.001
4	राजनीतिक सूचना-संपर्क	.198	.061	.167	3.246	.001
5	राजनीतिक चर्चा	.224	.056	.204	4.000	<.001
6	डिजिटल राजनीतिक सहभागिता	.173	.049	.156	3.531	<.001
7	राजनीतिक प्रभावशीलता	.251	.060	.221	4.183	<.001
8	शिक्षा	.142	.055	.119	2.582	.010
9	आय	.097	.044	.101	2.205	.028
10	प्रतिनिधि-संपर्क	.154	.053	.128	2.906	.004

मॉडल सारांश: $R = .821$, $R^2 = .674$, समायोजित $R^2 = .663$, $F = 59.82$, $df = 9, 290$, $p < .001$

तालिका 7 में नागरिकों की समग्र बहुस्तरीय राजनीतिक सहभागिता को आश्रित चर मानकर बहु-प्रतिगमन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। मॉडल का $R=.821$ है, जो स्वतंत्र चरों और समग्र राजनीतिक सहभागिता के बीच मजबूत संयुक्त संबंध को दर्शाता है। $R^2=.674$ से संकेत मिलता है कि मॉडल में सम्मिलित स्वतंत्र चर समग्र राजनीतिक सहभागिता में लगभग 67.4 प्रतिशत परिवर्तनशीलता की व्याख्या करते हैं। समायोजित $R^2=.663$ है। $F=59.82$ तथा $p<.001$ होने के कारण संपूर्ण प्रतिगमन मॉडल सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जागरूकता का $\beta=.291$ है और $p<.001$ है। इस मॉडल में यह प्रमुख पूर्वानुमानकों में से एक है। स्थानीय राजनीतिक सहभागिता का $\beta=.218$ तथा राजनीतिक प्रभावशीलता का $\beta=.221$ है। दोनों का $p<.001$ है। इससे संकेत मिलता है कि स्थानीय स्तर पर सक्रियता तथा नागरिक की यह धारणा कि वह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, व्यापक राजनीतिक सहभागिता से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं। राजनीतिक चर्चा का $\beta=.204$ तथा सूचना-संपर्क का $\beta=.167$ है। दोनों चर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल राजनीतिक सहभागिता का $\beta=.156$ और $p<.001$ है, जो यह दर्शाता है कि डिजिटल माध्यमों से जुड़ाव को अन्य कारकों के साथ नियंत्रित करने के बाद भी समग्र राजनीतिक सहभागिता से महत्वपूर्ण संबंध प्राप्त होता है। शिक्षा का $\beta=.119$ तथा आय का $\beta=.101$ है। इनके p-मूल्य क्रमशः .010 और .028 हैं, अतः दोनों स्वतंत्र चर मॉडल में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बने रहते हैं। प्रतिनिधि-संपर्क का $\beta=.128$ और $p=.004$ है, जो विशेष रूप से स्थानीय राजनीतिक अनुभव और व्यापक राजनीतिक सहभागिता के बीच संबंध की ओर संकेत करता है। इस प्रकार प्रतिगमन विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक जागरूकता, स्थानीय सहभागिता, राजनीतिक प्रभावशीलता, राजनीतिक चर्चा, सूचना-संपर्क, डिजिटल सहभागिता, शिक्षा, आय तथा प्रतिनिधि-संपर्क—सभी मिलकर नागरिकों की बहुस्तरीय राजनीतिक सहभागिता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान

दे सकते हैं। विशेष रूप से स्थानीय राजनीतिक अनुभव और व्यापक राजनीतिक सूचना के बीच संबंध इस अध्ययन के केंद्रीय शोध प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है।

चर्चा

अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता को केवल मतदान के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। स्थानीय स्तर पर मतदान और स्थानीय संस्थाओं की जानकारी अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, जबकि ग्राम सभा में नियमित उपस्थिति, स्थानीय बजट की जानकारी, विकास निर्णयों में भागीदारी तथा बैठक में अपनी राय व्यक्त करने जैसे सक्रिय सहभागिता के रूप अपेक्षाकृत कम पाए गए। यह निष्कर्ष वर्तमान संस्थागत संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय ने 2026 में ग्राम सभा में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन प्रकाशित किया है।

राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप अधिक मीडिया एवं डिजिटल माध्यमों से जुड़ा हुआ पाया गया। राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता का माध्य स्थानीय और राज्य सहभागिता की तुलना में अधिक था। निर्वाचन आयोग के 2024 के आँकड़ों में 66.10 प्रतिशत लोकसभा मतदान दर्ज किया गया, जो चुनावी सहभागिता के व्यापक स्वरूप को दर्शाता है। हालांकि अध्ययन के परिणाम यह भी दिखाते हैं कि मतदान के अतिरिक्त राजनीतिक चर्चा, नीति संबंधी जानकारी, प्रतिनिधियों से संपर्क तथा ऑनलाइन राजनीतिक गतिविधियाँ राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण घटक हैं।

शिक्षा के आधार पर राजनीतिक सहभागिता में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। उच्च शिक्षा वाले उत्तरदाताओं में राजनीतिक सहभागिता का औसत अपेक्षाकृत अधिक था। इसी प्रकार राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक सूचना-संपर्क और डिजिटल सूचना के उपयोग के उच्च स्तर वाले उत्तरदाताओं में समग्र राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई गई। सहसंबंध परिणामों ने भी राजनीतिक जागरूकता तथा राजनीतिक सहभागिता के बीच सकारात्मक संबंध को समर्थन दिया।

एक महत्वपूर्ण परिणाम स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय सहभागिता के बीच सकारात्मक संबंध है। इससे यह संकेत मिलता है कि स्थानीय राजनीतिक अनुभव व्यापक राजनीतिक नागरिकता से अलग-थलग प्रक्रिया नहीं है। स्थानीय समस्याओं, प्रतिनिधियों और विकास योजनाओं से संपर्क नागरिकों को व्यापक राजनीतिक मुद्दों की ओर ले जाने वाली एक संभावित प्रक्रिया हो सकता है। फिर भी सहसंबंधात्मक परिणामों को कारण-कार्य संबंध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

डिजिटल राजनीतिक सहभागिता का राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता के साथ संबंध स्थानीय सहभागिता की तुलना में अधिक पाया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि सामाजिक माध्यम और इंटरनेट व्यापक राजनीतिक मुद्दों से नागरिकों के संपर्क को बढ़ा सकते हैं। साथ ही, डिजिटल माध्यमों से प्राप्त सूचना की गुणवत्ता और सत्यापन को राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन में महत्वपूर्ण मानना आवश्यक है।

परिकल्पनाओं का औचित्य

परिकल्पना 1-**शून्य परिकल्पना H_{01}** : स्थानीय राजनीतिक सहभागिता तथा राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। सहसंबंध विश्लेषण में स्थानीय एवं राज्य राजनीतिक सहभागिता के बीच $r = .58$, $p < .001$ तथा स्थानीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक सहभागिता के बीच $r = .49$, $p < .001$ पाया गया। दोनों संबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। अतः निर्धारित सांख्यिकीय मानदंड के आधार पर शून्य परिकल्पना H_{01} **अस्वीकृत** की जाती है। परिणाम स्थानीय राजनीतिक सहभागिता और व्यापक राजनीतिक सहभागिता के बीच महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध की ओर संकेत करता है।

परिकल्पना 2-**शून्य परिकल्पना H_{02}** : विभिन्न शैक्षिक स्तरों के नागरिकों की औसत राजनीतिक सहभागिता में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। शिक्षा के आधार पर $F = 10.86$, $p < .001$ प्राप्त हुआ। अशिक्षित उत्तरदाताओं का औसत 2.71 तथा स्नातकोत्तर एवं अधिक शिक्षित उत्तरदाताओं का औसत 3.71 था। p -मूल्य .05 से कम होने के कारण शैक्षिक समूहों में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। अतः H_{02} **अस्वीकृत** की जाती है।

परिकल्पना 3-**शून्य परिकल्पना H₀₃**: राजनीतिक सूचना-संपर्क, राजनीतिक चर्चा और डिजिटल राजनीतिक सहभागिता समग्र राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण पूर्वानुमानक नहीं हैं। प्रतिगमन विश्लेषण में राजनीतिक सूचना-संपर्क का $\beta=.167$, राजनीतिक चर्चा का $\beta=.204$ तथा डिजिटल राजनीतिक सहभागिता का $\beta=.156$ पाया गया। तीनों के p-मूल्य .05 से कम हैं। संपूर्ण मॉडल भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण रहा, $R = .821$, $R^2 = .674$, $F = 59.82$, $p < .001$ । इसलिए H₀₃ **अस्वीकृत** की जाती है। परिणाम यह संकेत देता है कि ये तीनों चर समग्र राजनीतिक सहभागिता की व्याख्या में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता एक बहुआयामी एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया है। स्थानीय शासन से राष्ट्रीय राजनीति तक सहभागिता का स्वरूप केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक जागरूकता, स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी, प्रतिनिधियों से संपर्क, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा, सूचना प्राप्त करना और डिजिटल माध्यमों से राजनीतिक अभिव्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

स्थानीय स्तर पर नागरिकों की सहभागिता मुख्यतः चुनाव, स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क तथा विकास संबंधी जानकारी के रूप में दिखाई देती है, जबकि ग्राम सभा में नियमित उपस्थिति, स्थानीय बजट की जानकारी और निर्णय-निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देती है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया, इंटरनेट और सामाजिक माध्यम राजनीतिक सूचना एवं सहभागिता के महत्वपूर्ण साधन बनते दिखाई देते हैं। अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्थानीय और व्यापक राजनीतिक सहभागिता के बीच सकारात्मक संबंध है। इससे स्थानीय लोकतांत्रिक अनुभव को नागरिकों की व्यापक राजनीतिक नागरिकता के संदर्भ में देखने का आधार मिलता है। शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक चर्चा, सूचना-संपर्क, राजनीतिक प्रभावशीलता और डिजिटल सहभागिता भी समग्र राजनीतिक सहभागिता से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित पाए गए। अतः राजनीतिक सहभागिता को समझने के लिए केवल चुनावी आँकड़ों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। स्थानीय लोकतंत्र, नागरिक संवाद, प्रतिनिधि-संपर्क और डिजिटल नागरिकता को एक संयुक्त ढाँचे में समझना आवश्यक है। भविष्य के अध्ययनों में विभिन्न राज्यों, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों, आयु समूहों तथा सामाजिक वर्गों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही डिजिटल राजनीतिक सूचना की विश्वसनीयता, राजनीतिक प्रभावशीलता और स्थानीय संस्थाओं में वास्तविक निर्णय-निर्माण सहभागिता को अधिक गहराई से अध्ययन करना उपयोगी होगा।

संदर्भ सूची

- [1]. Dalton, R. J. (2008). *Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies* (5th ed.). CQ Press.
- [2]. Election Commission of India. (2025). *Atlas: General elections to Lok Sabha 2024*. Election Commission of India.
- [3]. Election Commission of India. (2025). *General election to Lok Sabha 2024: Statistical and electoral participation data*. Election Commission of India.
- [4]. Fox, S. (2014). Is it time to update the definition of political participation? Political participation in Britain: Evidence from the Audit of Political Engagement. *Parliamentary Affairs*, 67(4), 823–842.
- [5]. Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton University Press.
- [6]. Ministry of Panchayati Raj. (2022). *National capability building framework for Panchayati Raj institutions*. Government of India.
- [7]. Ministry of Panchayati Raj. (2025). *Basic statistics of Panchayati Raj institutions*. Government of India.
- [8]. Ministry of Panchayati Raj. (2026). *National study report: Low participation in Gram Sabha across the States and Union Territories* (Vol. I). Government of India.
- [9]. Ministry of Panchayati Raj. (2026). *National study report: Low participation in Gram Sabha across the States and Union Territories* (Vol. II). Government of India.
- [10]. Norris, P. (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.

- [11]. Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- [12]. Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- [13]. Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. Harper & Row.
- [14]. Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J.-O. (1978). *Participation and political equality: A seven-nation comparison*. Cambridge University Press.
- [15]. Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*. Cambridge University Press.